

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

समक्ष

श्री एम०के०सिंह

सदस्य

पुनरावलोकन प्रकरण क्रमांक 873-II/2014 - विरुद्ध आदेश दिनांक 6-11-2013  
पारित द्वारा - सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर - प्रकरण क्रमांक 2354-पीबीआर/13

विवा हाईवेज प्रा०लि० कंपनी बोरगांव बुजुर्ग  
पंधाना जिला खण्डवा तर्फे महेश बोरसे व संजय  
कांकरिया पता अशोका मार्ग, अशोका हाउस,  
बडाला, नासिक

--- आवेदक

विरुद्ध

1- म०प्र०शासन द्वारा

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)पंधाना  
जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा

---अनावेदक

(आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ~~दी. टी. बुफ्त~~)

(शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता श्री ~~चमिन्दु शुक्ला~~)

आ दे श

(आज दिनांक 21-5-2015 को पारित)

यह पुनरावलोकन आवेदन न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 2354-  
पीबीआर/2013 में पारित आदेश दिनांक 6 नवम्बर 2013 के विरुद्ध म०प्र०भू राजस्व  
संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 2354-  
पीबीआर/2013 में पारित आदेश दिनांक 6 नवम्बर 2013 से आवेदक द्वारा प्रस्तुत  
निगरानी निरस्त की गई है जिसके विरुद्ध यह पुनरावलोकन आवेदन इस आधार पर  
प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम बोरगांव बुजुर्ग तहसील पंधाना जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा  
की भूमि खसरा नंबर 1546 रकबा 17.43 हैक्टर में से 2.53 हैक्टर पर गौण खनिज हेतु

ख

दिया

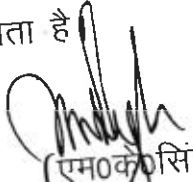
कंपनी को पट्टा दिया गया था किन्तु कंपनी द्वारा अन्य स्थान पर अवैध मुरम उत्खनन किया गया है। दिनांक 14-5-13 एवं 24-5-13 को कंपनी के कारिन्दा महेश बोरसे एवं संजय कांकरिया को कारण बताओ नोटिस जारी हुये हैं जिसमें विचारण न्यायालय ने कंपनी की ओर से नियुक्त अभिभाषक का निवेदन अस्वीकार करके न तो प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों की प्रति प्रदाय की गई और न ही पर्याप्त एवं युक्तियुक्त अवसर उत्तर प्रस्तुत करने हेतु दिया गया। कंपनी की ओर से नियुक्त अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत मेमो आफ अपिरियंस को भी गलत ढंग से खारिज कर दिया गया एवं प्रकरण में मात्र दो दिन का समय उत्तर प्रस्तुत करने एवं सुनवाई हेतु दिया गया। पेशी 31-5-2013 नियत की गई जबकि कंपनी के कर्मचारी महेश बोरसे को सूचना पत्र 24-5-13 को दिया गया। कंपनी को बचाव के लिये युक्तियुक्त अवसर भी नहीं दिया गया और यही तथ्य न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 2354- पीबीआर/2013 में आदेश दिनांक 6 नवम्बर 2013 पारित करते समय विचार में नहीं लिये गये, जिसके कारण रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओ सूचना विधिसम्मत न होने से निरस्त किये जाने तथा रिव्यु आवेदन स्वीकार करने की प्रार्थना की गई है।

3/ पुनरावलोकन आवेदन में वर्णित तथ्यों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं अनुविभागीय अधिकारी पंधाना के प्रकरण क्रमांक 3/67/2012-13 तथा न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 2354- पीबीआर/2013 के अवलोकन से स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी पंधाना ने आवेदक कंपनी के कर्मचारी महेश बोरसे व संजय कांकरिया को प्रथम कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 14-5-13 जारी करके पत्थर उत्खनन एवं मुरम उत्खनन करना बताते हुये बाजार मूल्य का चार गुना वसूली हेतु नोटिस जारी कर उत्तर तलब किया है तथा 28-5-13 को सुनवाई हेतु बुलाया है जबकि कंपनी की ओर से 21-5-13 को आवेदन प्रस्तुत कर संबंधित दस्तावेजों की प्रतियाँ उत्तर प्रस्तुत करने हेतु मांगी गई, अनुविभागीय अधिकारी पंधाना के प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है जिससे यह पता चल सके कि जिन आधारों पर कारण बताओ नोटिस दिनांक 14-5-12 जारी किया गया है, ऐसे कोई दस्तावेज कंपनी को अथवा उसके नियुक्त कारिन्दों को उपलब्ध कराये गये हों और जिन आधारों पर कंपनी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है ऐसे दस्तावेजों अर्थात् स्थल जांच रिपोर्ट, स्थल के

साक्षीगण के कथन अथवा पंचनामा आदि की प्रतियाँ जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उनकी प्रतियाँ कंपनी को अथवा उसके नियुक्त कारिन्दाओं को देना अनिवार्य थी जो नहीं देना पाया गया है। इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नोटिस दिनांक 14-5-13 के संलग्न स्थल जांच रिपोर्ट, स्थल के साक्षीगण के कथन अथवा पंचनामा आदि की प्रतियाँ नहीं भेजना एवं कंपनी के चाहे जाने पर उपलब्ध न करना अनुविभागीय अधिकारी पंधाना की कार्यवाही को दूषित होना माना जावेगा और जब अनुविभागीय अधिकारी पंधाना द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/67/2012-13 में की गई प्रारंभिक कार्यवाही ही दूषित है, उनके द्वारा कंपनी के विरुद्ध पारित आदेश भी दूषित श्रेणी में माना जावेगा, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी पंधाना द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/67/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 11-6-13 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी पंधाना द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/67/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 11-6-13 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। तदनुसार पुनरावलोकन स्वीकार किया जाता है।

  
(एम०के०सिंह)

सदस्य

राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर